

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 299/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- भोजराज सिंह पुत्र धन्नेसिंह 2- राणीदान सिंह पुत्र लाल सिंह 3- रूपसिंह पुत्र शंरसिंह 4- भीमसिंह पुत्र जेठमल सिंह 5- तेजसिंह पुत्र सगतसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण गांव रिडमलसर तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2017/ 906 दिनांक 24-7-2017 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री मोतीसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की ओर से ।
- 2- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30-8-2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार फलोदी ने ग्राम खारिया से संबंधित रास्तो की समस्याओं के निराकरण के प्रस्ताव जिनमे ग्राम खारियो के खरारा नंबरान 32, 30, 20, 21 व 23 मे ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू है, परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही है, जिनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाने हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश क्रमांक राजस्व/2017/ 906 दिनांक 24-7-2017 के जरिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अधीन तहसीलदार फलोदी के प्रस्ताव मे उल्लेख अनुसार खरारा नंबरान की भूमि की किस्म बारानी तृतीय से गै.मु.रास्ता के रूप मे परिवर्तन करने तथा नक्शा (लट्टा) ट्रेस मे उसके अनुसार दुरस्ती कर राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरागद करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता कायम करने, कटान करने अथवा रास्ता घोषित करवाने के संबंध मे किसी भी खातेदार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही हुआ था, केवल पटवारी एवं तहसीलदार ने अपनी गनमर्जी से अपीलाण्टगण की भूमि मे से रास्ता घोषित करने का प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तहसीलदार फलोदी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये खातेदारी की भूमि मे से



अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

गै0मु0रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के खातेदारान को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई तथा उनको सुने बिना ही अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि का रकबा कम कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

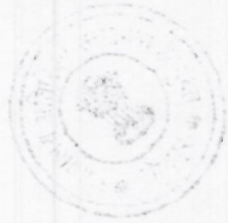
वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 24-7-17 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त आदेश में राज्य सरकार के किसी परिपत्र अथवा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश का उल्लेख नहीं किया हुआ है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त अपीलाधीन आदेश रास्ते संबंधी समस्याओं के निवारण अभियान के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, इसलिए अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जाने का प्रावधान है, वर्तमान मामले में राजस्व रिकॉर्ड में ऐसी कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं होने पर भी जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि किसी खातेदार को रास्ता दिया जाना या कायम करवाया जाना है तो उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 एवं 251ए के तहत विधिवत कार्यवाही करने के लिए कानून में अलग व्यवस्था दे रखी है इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि यदि सरकार को भी रास्ते के लिए भूमि की आवश्यकता है तो विधिवत भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्बन्धित खातेदारान को नोटिस देकर भूमि अवाप्ति की विहित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान उपलब्ध होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने केवल शॉर्ट कट रास्ता अपनाते हुए बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के ही पारित कर दिया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी होते ही उक्त अपील इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर दी थी जिसे स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-7-2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण एवं अन्य हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, गौका निरीक्षण कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

रेस्पों0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तों की



अति - अनवान भोजराज सिंह
नोडर

समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के दौरान तहसीलदार फलोदी ने राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नंबरान में से चल रहे रास्तों का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा अपने खेतों में आने जाने के हेतु लिया जा रहा था परंतु उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने से जनहित में उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु विधिवत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करने पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध पत्रादि एवं तहसीलदार फलोदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित रास्तों की समस्याओं के निराकरण प्रस्ताव तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2017/906 दिनांक 24-7-17 आदि का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार फलोदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित प्रस्ताव जिनमें निजी खातेदारों की भूमि में से मौके पर स्थाई रास्ते बालू हैं परंतु उनका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं होने का उल्लेख होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तावित रास्ते की भूमि के किसी खातेदार को, उसके खातेदारी में से चल रहे रास्ते की भूमि का इन्द्राज गै.मु.रास्ता दर्ज करने के संबंध में सूचना या नोटिस दिया जाना प्रकट नहीं होता है, इससे यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-17 बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो नेचुरल जरिट्स के विरुद्ध होने से समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-7-2017 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त आदेश में राज्य सरकार के किसी परिपत्र एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के किसी आदेश का उल्लेख नहीं किया हुआ है जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तों की समस्याओं के निराकरण अभियान के दौरान ही राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में ही पारित किया गया हो क्योंकि खातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। परंतु राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान के दौरान अभियान अवधि तक ऐसी शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रदत्त की जाती हैं इसलिए अपीलाधीन आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र, आदेश तथा दिनांक का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया जाना नितान्त आवश्यक था, जो नहीं किया हुआ होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

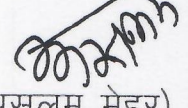
उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांतगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2017/906 दिनांक 24-7-17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस

शक्ति - सरभोग्य आयुक्त
जोधपुर

निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वर्तमान अपील के अपीलांटगण एवं अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान एवं अन्य हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा मौके की स्थिति की जानकारी रेकॉर्ड पर ली जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।



निर्णय आज दिनांक 30-8-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।


(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर